of every cotton season subject to the adjustments being made after detailed Crop estimates are available. During the current cotton season, the Government has so far released 14.955 lakh bales of cotton for export.

The major problem in regular exports of cotton is that the production level of cotton is not stable because the crop size varies in the rainfed conditions. Besides, the Government has to remain alive to the problems faced by the decentralised handloom sector and, therefore, Government releases only the exportable surplus after ascertaining the total availability and after meeting the requirements of domestic textile industry including the handloom and powerloom sectors.

The Government is making efforts to augment the cotton production through intensive cotton development programme under the Ministry of Agriculture.

टेलीफोन कनेक्शनों का उपलब्ध किया जाना

*449. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-ओ.वाई. टी. श्रेणी के आवेदकों को पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कितने टेलीफोन केन्द्रों में गैर-ओ०वाई०टी० श्रेणी के अन्तर्गत पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी हां, आवेदकों को टेलीफोन, विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत उनकी पंजीकरण की तारीख के क्रम में प्रदान किए जा रहे हैं जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

विचाराधीन पड़े (बैकलाग) टेलीफोन कनेक्शनों को, आठवीं योजना (92–97) के दौरान उत्तरोत्तर रूप से निपटाने का प्रस्ताव है जिसमें ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग होने पर व्यवहारिक रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने और बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीक्षा अवधि को 2 वर्ष तक सीमित रखने की परिकल्पना की गई है।

(ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Doing away with the concept of Nominee Directors on Nationalised Banks

*450. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to do away with the concept of Nominee Directors of the Reserve Bank of India on the Boards of Nationalised Commercial Banks;

(b) if so, what are the details of the proposal;

(c) whether it is a fact that RBI Nominee Directors on the Boards of these banks make direct intervention in their operations;

(d) whether Government have received any representations or suggestions from the nationalised banks in this regard; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE